

कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाना

प्रीलमिस के लिये:

मुदा सवासथय कारड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFVY), राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM), सूक्ष्म सचिवाई कोष (MIF), राष्ट्रीय संवहनीय कृषि भिशन (NMSA), नैनो यूरथी

मेंस के लिये:

आरथिक रूप से व्यवहार्य कृषि महत्व, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

यह एडिटोरियल 17/05/2023 को 'हंडि बजिनेस लाइन' में प्रकाशित "Agriculture needs a 'natural' boost" लेख पर आधारित है। इसमें आरथिक रूप से व्यवहार्य कृषि के महत्व के बारे में चर्चा की गई है और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुछ संभावित नीतिगत उपायों के सुझाव दिये गए हैं।

भारत सरकार खेती को अधिक आरथिक रूप से व्यवहार्य और संवहनीय बनाने की आवश्यकता से अवगत रही है। कम उत्पादकता, उच्च इनपुट लागत, बाजार में उत्तार-चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और संस्थागत समर्थन की कमी जैसी कृषकों के समक्ष विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये सरकार कई उपाय कर रही है। भारत की समग्र अरथव्यवस्था और समाज के लिये कृषि क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है और देश की आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार लाना भारत में नीतिनिर्माताओं के लिये एक प्राथमिकता और एक चुनौती, दोनों ही रही है।

कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाना क्यों महत्वपूर्ण है?

- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिति करने के लिये:** भारत एक विशाल आबादी वाला देश है जहाँ खाद्य की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सुनाश्चिति करने के लिये किसी के पास प्रयाप्त खाद्य उपलब्ध हो, कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य (economically viable) बनाना महत्वपूर्ण है ताकि किसान मांग की पूरति के लिये प्रयाप्त खाद्य का उत्पादन कर सकें।
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना:** कृषि ग्रामीण अरथव्यवस्था के लिये प्रमुख योगदानकर्ता है। कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाना संभव है।
- अधिकांश भारतीयों की आजीविका का समर्थन करने के लिये:** कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाने से उन लाखों भारतीयों के जीवन स्तर और रहन-सहन में सुधार करने में मदद मिल सकती है जो अपने अस्ततित्व के लिये खेती पर निरिभर हैं। कृषि प्रत्यक्ष रूप से भारत की 50% से अधिक आबादी के लिये आय और रोजगार का मुख्य स्रोत है।
- अरथव्यवस्था के विकास और स्थरिता को बढ़ाने के लिये:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान लगभग 17-18% है। कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, अपव्यय (wastage) की कमी, फसलों के विधिकरण, मूलयवर्धन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिति करने के रूप में भारत के समग्र आरथिक विकास एवं स्थरिता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- सतत और प्राकृतिक खेती अभ्यासों को अपनाने के लिये:** कृषि प्रयावरणीय क्षमता, जल की कमी, मृदा क्षरण और गरीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण बनती है। वर्तमान कृषि अभ्यास हानिकारक रसायनों, सचिवाई की अपव्यय और सबसंज्ञी पर निरिभर बने हुए हैं। कृषि को आरथिक रूप से व्यवहार्य बनाने से सतत और प्राकृतिक कृषि अभ्यासों को बढ़ावा मिल सकता है जो प्रयावरणीय प्रभाव को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ाते हैं।

सन्नहिति चुनौतियाँ

- डिजिटल साक्षरता का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान स्मार्टफोन या विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच का अभाव रखते हैं, जो डिजिटल कृषि सेवाओं तक पहुँच की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता एक अन्य चुनौती है जो किसानों द्वारा नई तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों को समझने के लिये आवश्यक है।

- **छोटी जोत:** भारत में कसिनों की एक बड़ी संख्या छोटी जोत (small land holdings) रखती है, जो आकारकि मतिव्ययता (economies of scale) परापृत करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है और उनकी लाभप्रदता को कम कर सकती है।
- **ऋण तक पहुँच का अभाव:** भारत में कई कसिनों की औपचारकि क्रेडिट या साथ तक पहुँच नहीं है, जो खेतों में नविश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार लाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **बाजारों तक पहुँच का अभाव:** भारत में कसिनों की एक बड़ी संख्या की बाजारों तक पहुँच नहीं है जहाँ वे अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें। इससे कसिनों को उनकी उपज के लिये कम कीमत परापृत होने और उनकी लाभप्रदता कम होने की स्थितिबिनती है।
- **जलवायु परविरतन:** जलवायु परविरतन के परणिमस्वरूप सूखा और बाढ़ जैसी बारंबार और चरम मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति हो रही है, जिनका कसिनों की आजीविका पर वनिशकारी परभाव पड़ सकता है।
- **अवसंरचना की कमी:** भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बजिली और सचिर्लाई परणाली जैसी बुनियादी अवसंरचना का अभाव है, जो कसिनों की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** भारत बाढ़, सूखा और कीटों के प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिये प्रवण है। ये आपदाएँ फसलों और पशुधन को क्षति पहुँचा सकती हैं, जिससे कसिनों को हानि हो सकती है।
- **अकृष्ण विधियां:** भारत में कृष्णिउपज के लिये विधियां परापृत सक्षम नहीं हैं। इससे कसिनों के लिये कम कीमत और उपभोक्ताओं के लिये उच्च कीमतों की स्थितिबिनती है।

सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें

- **मूदा स्वास्थ्य कारड योजना (Soil Health Card Scheme- SHCS):** इसका उद्देश्य कसिनों को उनकी मूदा के पोषक तत्वों और उत्परता की स्थितिकि बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिये देश भर के कृषक्षेत्रों में मूदा स्वास्थ्य का आकलन करना और उनमें सुधार लाना है। इससे कसिनों को सूचना-संपन्न नियम लेने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है और लागत कम होती है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** यह विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हानिया क्षतिकि स्थितिमें कसिनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सचिर्लाई योजना (PMKSY):** इसका उद्देश्य सचिर्लाई नविश में वृद्धि, खेती योग्य क्षेत्रों के विस्तार, जल उपयोग दक्षता में सुधार, परशुरुद्ध सचिर्लाई एवं अन्य जल-बचत तकनीकों को अपनाने और सतत जल संरक्षण अभ्यासों को बढ़ावा देने के माध्यम से कृष्णिउत्पादकता एवं कृषि कार्यों में जल संसाधन उपयोग की स्थितिमें सुधार लाना है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agriculture Market- e-NAM):** यह एक अखलि भारतीय इलेक्ट्रॉनिकि ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के नियम हेतु मौजूदा APMC मंडलियों को परस्पर-संबद्ध करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):** वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय विकास योजना एक छत्र योजना है जो समग्र कृषि और संबद्ध सेवाओं के विकास को सुनिश्चित करती है। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध सेवाओं में सार्वजनिक नविश बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- **सूक्ष्म सचिर्लाई कोष (Micro Irrigation Fund- MIF):** सूक्ष्म सचिर्लाई के तहत कवरेज के विस्तार के लिये अतरिकित संसाधन जुटाने और 'प्रधानमंत्री कृषि सचिर्लाई योजना - प्रति बूँद अधिकि फसल' के प्रावधानों से परे इसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 2019-20 में नाबाड़ (NABARD) के अंतरगत MIF की स्थापना की गई।
- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA):** इस मिशन को एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मूदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विशेष रूप से वर्षा-सचिति क्षेत्रों में कृष्णिउत्पादकता बढ़ाने के लिये तैयार किया गया है।
 - वर्षा-सचिति क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development- RAD): यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परविरतन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System- IFS) पर केंद्रित है।
 - मूदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management- SHM): यह अवस्थितिकि साथ-साथ फसल विशिष्ट सतत मूदा स्वास्थ्य प्रबंधन (अवशिष्ट प्रबंधन और जैवकि कृषि अभ्यास सहित) को बढ़ावा देने के लिये मूदा उत्परता मानचित्रों को मैक्रो-माइक्रो पोषक तत्व प्रबंधन के साथ संबद्ध करने पर लक्षित है।

कृषि को आरथकि रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये कौन-से नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं?

- **कृषि डिजिटलीकरण:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकि आधारति कृषि स्टार्ट-अप कसिनों के लिये बीज से लेकर बाजार तक फुल-स्टैक समाधान (full-stack solutions) प्रदान करते हैं। वे आपूरता, ऋण, बीमा और सर्वोत्तम मूल्य पर अपनी उपज की बिक्री करने के लिये प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान कर कसिनों को प्राथमिकता देते हैं।
 - उदाहरण के लिये, गुरुवाराम स्थिति 'देहात' (DeHaat) 35 से अधिकि फसलों को दायरे में लेते हुए 15 लाख कसिनों को कृत्रिम बुद्धिमित्ता (AI), मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सेवा प्रदान करता है।
 - समार्टफोन की सुविधा रखने वाले कसिनों कृषि-इनपुट, कृषि सिलाह और कृषि-उपज के विधियां के लिये डिजिटलीकृत कृषि-सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **एकीकृत/प्राकृतिक खेती (Integrated/Natural Farming):** छोटी जोत वाले कसिनों के लिये एकीकृत खेती लाभदायक सदिध हो सकती है। प्राकृतिक खाद के लिये कुछ पशुओं, मत्स्य तालाब एवं वर्षा-कल्चर से संपन्न नविश आत्मनियम और आरथकि रूप से सशक्त बन सकते हैं। इस प्रकार की खेती के लिये पारविरकि शरम महत्त्वपूरण है और यह व्यावसायिकि रूप से व्यवहार्य एवं प्रयावरण की दृष्टि से संवहनीय है।
 - प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर और बाहरी इनपुट की आवश्यकता को नयनतम कर खाद्य असुरक्षा, कसिनों के संकट, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रदान करती है।

- जलवायु-कुशल कृषि:** जलवायु-कुशल कृषि (Climate Smart Agriculture) **नैनो यूरिया** जैसे प्रयोगरण के अनुकूल कृषि-इनपुट की ओर आगे बढ़कर कृषि को आरथकि रूप से व्यवहार्य बना सकती है। यह उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम कर सकती है जो अपूरणीय पारस्थितिकि कृष्टि, मृदा अनुरवरता और विषाक्त खाद्य शृंखला का कारण बन सकते हैं। कसिन लागत-प्रभावी और सतत कृषि अभ्यासों का उपयोग कर अपनी इनपुट लागत को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इससे कृषि को दीर्घावधि में अधकि लाभदायक और संवहनीय बनाने में मदद मलि सकती है।
 - सरकार उर्वरक सबसडि पर भारी व्यय करती है। इसके कारण उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की स्थिति बनती है, जिसके परणामस्वरूप अपूरणीय पारस्थितिकि कृष्टि, मृदा अनुरवरता और विषाक्त खाद्य शृंखला जैसे परणाम उत्पन्न होते हैं।
 - पंजाब में मृदा असवास्थयकर स्थिति में है जहाँ राष्ट्रीय औसत 135 कलिग्राम की तुलना में प्रतिहेकटेर 246 कलिग्राम उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
- सर्वोत्तम कृषि अभ्यासों को अपनाना:** सहकारी सदिधांतों पर आधारति सर्वोत्तम कृषि अभ्यासों को अपनाना कृषि को आरथकि रूप से व्यवहार्य बना सकता है। उदाहरण के लिये, इज़राइल अपनी प्रतिकूल जलवायु और सीमति संसाधनों के बावजूद कृषि-उपज के एक प्रमुख नरियातक और कृषि प्रौद्योगिकियों में वैश्वकि स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। सर्वाधिकि उत्पादक तरीके से कृषि आउटपुट के सूजन के लिये सामाजिकि समानता, सहकार्यता एवं पारस्परकि सहायता का पालन करके कसिन अपनी दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इससे दीर्घावधि में लाभप्रदता और संवहनीयता की वृद्धि हो सकती है।
- अनौपचारकि ऋण लेने से बचना:** औपचारकि ऋण तक आसान पहुँच बनाने के अलावा, कसिनों को वित्तीय विविक पर प्रामरश देने की आवश्यकता है। औपचारकि ऋण सुवधाएँ कसिनों को उनके खेतों में नविश के लिये धन उपलब्ध कराकर कृषि-उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ा सकती है।
 - हाल के एक सर्वेक्षण से पुष्टि होती है कि वित्ति के औपचारकि स्रोतों की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण भारत में अभी भी साहूकारों/व्यापारियों/जमीदारों का अस्ततिव बना हुआ है, जो कसिनों को आरथकि रूप से अस्थरि तथा अनौपचारकि ऋण स्रोतों पर नरियर बनाए रखता है।
- कृषि मूल्य शृंखलाओं का विकास:** कृषि मूल्य शृंखलाओं (Agri-Value Chains) के प्रमुख चालक हैं- ग्राहक फोकस, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, प्रशक्षण और कृषमता नरियाण।
 - महाराष्ट्र स्थिति एक बहु-राज्यीय कसिन उत्पादक कंपनी 'VAPCOL' का उदाहरण लिया जा सकता है। सात राज्यों में वसितृत 40,000 से अधकि आदविसी कसिनों को दायरे में लेने वाले 55 कसिन उत्पादक संगठन (FPOs) इसके सदस्य हैं।
- समूहों (Collectives) का लाभ उठाना:** SHGs, कसिन उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समतियों के अभसिरण से रयायती मूल्य पर इनपुट की थोक खरीद, परविहन एवं भंडारण में आकारकि मतिव्ययता, नमिन-लागत संस्थागत वित्त तक पहुँच, कृषि मिशीनीकरण (फसलों की नगरानी और उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों आदकि छिकाव के लिये ड्रोन) आदमामलों में कसिनों की बहतर सौदेबाजी शक्ति को बढ़ावा मलिगा।

अभ्यास प्रश्न: भारत में लाखों कसिनों की आजीवकि को सुनिश्चिति करने के लिये कृषि को आरथकि रूप से व्यवहार्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। आरथकि व्यवहार्यता प्राप्त करने में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक उपायों के सुझाव दें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्र. क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये:

- भारत में 'क्लाइमेट-स्मार्ट वलिज' दृष्टिकोण जलवायु परविरतन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS) के नेतृत्व वाली एक परयोजना का एक हस्सा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम है।
- CCAFS की परयोजना फ्रांस में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (CGIAR) के तहत की जाती है।
- भारत में अर्द्ध-शुष्क उषणकटिबंधीय के लिये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्र. नमिनलखिति युग्मों पर वचार कीजिये: (2014)

कार्यक्रम/परयोजना : मंत्रालय

- सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम : कृषि मंत्रालय
- मरुस्थल विकास कार्यक्रम : प्रयोगरण एवं वन मंत्रालय
- वर्षापूरति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलसम्भर विकास परयोजना : ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (d)

Q. भारत में, नमिनलखिति में से कनिहें कृषि में सार्वजनिक नविश माना जा सकता है।

1. सभी फसलों के कृषिउत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि सिख समतियों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूँजी विकास
4. कृषकों को निःशुल्क बजिली की आपूरति
5. बैंकिंग परणाली द्वारा कृषित्रिट्रण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागर सुविधाओं को स्थापित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

?/?/?/?/? ?/?/?/?/?/? :

प्रभारतीय कृषि में प्रकृति की अनश्विचतिताओं पर निरभरता के मददेनजर, फसल बीमा की आवश्यकता की विचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) की मुख्य वशिष्टताओं का उल्लेख कीजिये। (2016)

Q. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई वभिन्न प्रकार की करांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन करांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में कसि प्रकार सहायता प्रदान की है? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/making-agriculture-economically-viable>